whole House is seized of it and all hon. Members are entitled to take part in it. Under these circumstances, I would urge upon all hon. Members to treat these matters with greater attention than what is being done today. I would urge upon hon. Members to be present in the House.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): Even the Minister of Parliamentary Affairs did not collect his Members.

Mr. Speaker: What is he to do? Again and again Government is accused.

17.50 hrs.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY*

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): Sir, before the hon. Member starts the discussion I should like to inform the House that after I answered this question in December, the Aligarh University has appointed a committee to go into all the matters which were raised by the hon. Member and other questions which he referred to me privately. I do not know whether any useful purpose will be served by this discussion at this stage. In any case, it will be very difficult for me to say anything in the matter.

Shri Ansar Harvani (Fatehpur): Sir, on a point of order. In view of the fact that a committee has been appointed and it is making investigations, I think it will be unfair for the committee if we have discussions in this House. Therefore, I would request you to postpone the discussion till the committee submits its report.. (*Interruptions.*)

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): Sir, can anything which is on the agenda be postponed for extraneous considerations, which are not within the purview of this House?

Mr. Speaker: By whom was the committee appointed?

Dr. K. L. Shrimali: By the university.... (*Interruptions.*)

Mr. Speaker: The university committee is an internal affair. Members want to know the position and the debate also may help the committee to come to a conclusion one way or the other. The committee must know what the hon. Members know and what has come to their notice.

In the half-an-hour discussion, the opener of the discussion will have ten minutes. The hon. Minister will have 10-15 minutes. The other hon. Members who have given notice will each put one question or two.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, इस सीमित समय में मुझे अपनी बात सीमित भाषा में ही उपस्थित करनी पड़ेगी । मैं चाहता तो यह था कि विस्तार के साथ उसको उपस्थित करता ।

स्वतंत्र होने के पश्चात् भारत के विश्वविद्यालयों से जिस स्वच्छता की आशा की जाती थी, उसमें भारत का एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है । लेकिन पीछे कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं जो न केवल उक्त विश्वविद्यालय के लिये अपितु इस भारत राष्ट्र के लिये और इस संसद् के लिये भी दुर्भाग्य की सूचक हैं । मैं उन ही बातों को इस समय उपस्थित करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं उसी बात का उत्तर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कमेटी नियुक्त हो जाने के पश्चात् भी मुझे क्यों आवश्यकता पड़ी इस बात की कि मैं इन बातों की चर्चा इस सदन के अन्दर उठाऊं । असलियत यह है कि जो कमेटी नियुक्त हुई है वह विश्वविद्यालय की ओर से नियुक्त हुई है, और विश्वविद्यालय ऐक्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी इस कमेटी के एक मेम्बर होंगे । लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन सूचनाओं को मैं यहां पर देने के लिये जा रहा हूं वह विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर के खिलाफ ही हैं । जब वह वाइस चान्सलर

*Half-An-Hour Discussion.

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

उस कमेटी के एक सदस्य हैं तो जो कुछ व्यक्ति उनके विपरीत अपनी गवाही या प्रमाण उपस्थित करना चाहता है वह उनको उतनी निर्भीक या स्वतंत्र भाषा में उपस्थित नहीं कर पायेंगे । इसलिये मैं इस सारे कथन को उपस्थित करने के पश्चात् विशेष रूप से और बलवती भाषा में यह बात कहना चाहता हूं कि इस कमेटी के जो सदस्य हैं उनमें से यद्यपि मैं मानता हूं कि दो तीन सदस्य ऐसे हैं कि जिनकी दृढ़ता और पवित्रता का हमको विश्वास है, परन्तु मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह से हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में स्वतंत्र विजिटर कमेटी नियुक्त की गई थी उसी प्रकार से एक कमेटी इस अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी नियुक्त की जाये, और यदि किसी कारण से राष्ट्रपति की ओर से विजिटर कमेटी नियुक्त न की जा सके तो मेरा निवेदन है कि जब तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह कमेटी एन्क्वायरी करे, तब तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाइसचांस्लर को अलीगढ़ से हटा देना चाहिये अन्यथा उनके वहां रहते हुए यह कमेटी स्वतंत्रता से कोई निर्णय ले सकेगी इसमें हमको सन्देह है । लेकिन अगर यह चीज भी न हो सके तो यह काम अवश्य होना चाहिये कि इस कमेटी के सदस्य के तौर पर उक्त विश्वविद्यालय के वाइसचांस्लर इस कमेटी में न बैठ सकें । यदि आप इस कमेटी से सही और निष्पक्ष निर्णय चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है ।

अब मैं सीमित भाषा में विशेष रूप से वह बात उपस्थित करना चाहता हूं । जिन का इस प्रश्न से सम्बन्ध है ।

पहली बात तो यह है कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि सन् १९५३ में आडीटर जनरल ने शिक्षा विभाग को यह रिपोर्ट दी थी कि इस विश्वविद्यालय में बहुत सी अनियमितताएं पायी गई हैं । लेकिन उसके पश्चात् शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय को निदेश दिया गया कि आप उनकी जांच कराइए परन्तु विश्वविद्यालय उसको टालता रहा, टालता रहा ।

सन् १९५६ में आकर एक छोटी सी रिपोर्ट मिली । फिर उसके पश्चात् सितम्बर, १९५८ में शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर को हिदायत दी कि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में वित्तीय रिपोर्ट दें ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर ।

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) यह जो वाइसचांस्लर का जिक्र किया कि वह कमेटी के मेम्बर हैं, तो क्या सन् १९५३ में वह यूनीवर्सिटी में थे ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : वह सारी बातें भी आपके सम्मुख उपस्थित करना चाहूंगा कि वाइसचांस्लर महोदय के समय की घटनाएं क्या हैं । यदि आप दस मिनट का समय और बढ़ा दें तो शायद डिप्टी मिनिस्टर साहब को भी संतोष हो जाएगा कि क्यों मैं यह मांग उपस्थित कर रहा हूं ।

हां । तो सितम्बर, सन् १९५८ में शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर को हिदायत दी कि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में वित्तीय रिपोर्ट दें । फाइनेंशियल एडवाइजर ने सितम्बर, सन् १९५९ में एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने वहां की हालत बड़ी गम्भीर बताई और यह बताया कि ५० लाख रुपया जो मैडिकल कालेज का है उसको प्राइवेट तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और यह भी रिपोर्ट दी कि लाखों रुपया बट्टे खाते में डाल दिया गया है ।

इसी प्रकार की कुछ घटनाएं मैं आपको बताता हूं कि कुछ रुपया जो विश्वविद्यालय

का था वह यह कह कर बट्टे खाते डाल दिया गया कि ये लोग पाकिस्तान चले गये हैं इसलिये इस रुपये को खत्म कर दिया जाए । इस तरह की कुछ घटनाएं मैं आप को देता हूं-- यह बात विश्वविद्यालय के रिकार्ड में है ।

एक कर्नल मकबूल हुसैन कुरेशी, भोजन कक्ष के ठेकेदार हैं । इनके लिए आपने एक प्रश्न के उत्तर में पहली दिसम्बर, को यह बताया भी था कि यह ३५,२३५ रुपया एडवांस लेकर बहावलपुर में गेहूं खरीदने के लिए गये । विश्वविद्यालय की ओर से यह कहा जाता है कि हमने वहां पर मुकदमा चलाया लेकिन यह पैसा हमको नहीं मिल सका और विश्वविद्यालय उस मुकदमे में हार गया । पहली बात तो यह है कि जिस समय यह ३५,२३५ रुपया लेकर बहावलपुर गये थे तो क्या उनके पास कोई ऐसा परमिट था कि बहावलपुर से अलीगढ़ गेहूं लाया जा सकता था । दूसरी बात यह कि विश्वविद्यालय के जो लीगल एडवाइजर हैं और जो वहां के ला डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, वह जिस समय इस केस को लड़ने के लिये वहां पर गये तो जो पैसा विश्वविद्यालय की ओर से केस लड़ने के लिये दिया गया था तो क्या उसके लिए उनके पास एक्सचेंज परमिट था, क्या रिजर्व बैंक के द्वारा उन्होंने पाकिस्तान का एक्सचेंज प्राप्त कर लिया था । यदि नहीं प्राप्त कर लिया था तो जितना पैसा वह विश्वविद्यालय से ले गए थे वह किस प्रकार से खर्च हुआ इसके सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री हमको जानकारी दें ।

दूसरे व्यक्ति हैं अब्दुल हई, जो पहले य० पी० गवर्नमेंट के चीफ बाइलर इंस्पेक्टर आफ फैक्टरीज थे । उनके सम्बन्ध में भी यह कहा जाता है कि ३५,७६० रुपया साढ़े १४ आने उनके पास थे और उनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के खाते में यह लिख दिया गया कि वे पाकिस्तान चले गये इसलिये पैसा बट्टे खाते में डाल दिया जाए । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक वह व्यक्ति हिन्दुस्तान में है और प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री महोदय की ओर से यह कहा गया है कि इस पैसे को लेने की कोशिश की जा रही है । जब आपको यह पता है कि वह व्यक्ति कहां है और विश्वविद्यालय का इतना पैसा उसके पास है, तो क्यों नहीं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई ।

इसी प्रकार से एक सज्जन हैं शेख अबदुल्ला । उनके पास भी इसी तरह से महिला कालेज के भवन निर्माण के सम्बन्ध में ४६,७३४ रुपया ७ आना है । इसके लिये भी इसी प्रकार का प्रस्ताव पास कर दिया गया कि यह पाकिस्तान चले गये इसलिये यह पैसा बट्टे खाते के अन्दर डाल दिया जाए । यह सज्जन अभी तक अलीगढ़ में मौजूद हैं और उनकी लड़की विश्वविद्यालय की विमेन्स कालिज की प्रिंसिपल है ।

मैं सीमित भाषा में ही यह तमाम बातें कह रहा हूं क्योंकि आप अधिक समय नहीं दे रहे हैं ।

इसी प्रकार से डा० रईस अहमद हैं जिनके पास में ९,७४८ रुपये हैं ? पहले इस रकम को भी बट्टे खाते में डालने को कहा गया लेकिन २७ जनवरी, १९५७ को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने प्रस्ताव पास किया कि वाइस-चांसलर इस पैसे को लेने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं लिया जा सका और अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकी है ।

अब मैं आपको एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण सूचना देना चाहता हूं । सदन को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि विश्वविद्यालय के धन के लाखों रुपये के दुरुपयोग में केन्द्रीय सरकार के उच्चतम अधिकारी, विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेम्बर और वाइस-चांसलर जैसे प्रमख लोग सम्मिलित हैं ।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

विश्वविद्यालय के अन्दर एक मकान था जो कि बहुत साधारण कोटि का मकान था। जैसा कि नियम होता है, जब कोई प्रापर्टी खरीदी जाती है तो यह देखा जाता है कि इसको बने हुये कितने दिन हो गये, कुल प्रापर्टी का अगर इतना मूल्य था तो अगर इतने वर्ष बने हुये हो चुके हैं, अब कितना मूल्य समाप्त हो गया होगा और उसी हिसाब से मूल्य दिया जाता है। यहां केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग में एक उच्चतम अधिकारी हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं उनका नाम भी प्रस्तुत कर दूंगा वह शिक्षा विभाग के अन्दर सेक्रेटरी हैं। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो उनका नाम है मिस्टर मैयदेन। उनका अपना एक मकान है। वह बहुत साधारण कोटि का मकान है जिसकी मारकेट वैल्यू आठ दस हजार से अधिक नहीं होगी। चूंकि वह मकान विश्वविद्यालय के कम्पाउंड में है इसलिये दूसरा कोई व्यक्ति उसे ले भी नहीं सकता था। जिनका यह मकान है वह यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन के मैम्बर भी हैं, एजूकेशन विभाग के सेक्रेटरी हैं, इसलिये ३१,८८८ रुपये के अन्दर यह मकान उन्होंने बेचा। ३१,८८८ रुपये में मकान बेचने के पश्चात् जब यह स्थिति आयी कि चारों ओर चर्चा हुई कि पद का यह दुरुपयोग हुआ है। तो फिर विश्वविद्यालय के लोगों ने निश्चय किया कि इस मकान को जल्दी से ऐसी स्थिति में बना दो कि कोई व्यक्ति देखे तो यह न कहे कि इतनी भारी रकम इसके लिए नहीं दी जा सकती थी। विश्वविद्यालय ने निश्चय किया कि ६००० रुपये इसकी मरम्मत में लगा दिये जाएं। ६००० रुपये मरम्मत में लगाने का यह निश्चय हुआ लेकिन उस मकान में १३ हजार रुपये मरम्मत में खर्च किये गये।

इसी प्रकार से मैयदेन साहब के एक साले हैं साजिद साहब। उनकी बीवी के नाम से एक मकान उसकी बगल में है जो ७०,६४० रुपये की लागत से विश्वविद्यालय ने खरीदा है, जिसकी मारकेट वैल्यू २५-३० हजार से अधिक नहीं हो सकती, और यह भी इसी क्षेत्र के अन्दर इसी प्रकार की चीज है।

इसी तरह से विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेम्बर हैं जिनका नाम है मिस्टर ए० एम० ख्वाजा। उनकी एक जमीन है जो गवर्नमेंट प्रेस गवर्नमेंट आफ इंडिया का है उसके पास है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कुछ समय पीछे हमारे सरदार स्वर्ण सिंह जी जब पहले मिनिस्टर थे तो वह इस जमीन को लेना चाहते थे भारत सरकार की ओर से। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार वह इस जमीन को दस बारह आना प्रति स्क्वेयर गज के हिसाब से खरीदना चाहते थे लेकिन जिनकी जमीन है वह उसको एक रुपया गज के हिसाब से देना चाहते थे। बेगम ख्वाजा जिनके नाम वह जमीन है और जिनके पति एग्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर हैं। उन्होंने यह जमीन तीन रुपये प्रति स्क्वेयर गज के हिसाब से बेची है, जो कि कई लाख रुपये में विश्वविद्यालय ने खरीदी है। वहां पर इस प्रकार की चीज चल रही है।

18 hrs.

इसी प्रकार से रानीखेत में एक मकान खरीदा गया है। प्रश्न यह है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को रानीखेत में मकान खरीदने की क्या आवश्यकता है। जहां तक मेरी जानकारी है, यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है, उसके अनुसार कुछ माइलेज में इस प्रकार की सीमा निर्धारित है कि इतनी सीमा की प्रापर्टी यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव की परमिशन से खरीदी जा सकेगी और इस से जो अधिक होगी, उस के लिये विजिटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन रानीखेत का वह मकान

खरीदा गया केवल इसलिये कि जिस व्यक्ति का वह मकान है, वह उपकुलपति का एक मित्र है। इस लिये उस को एक भारी रकम—जैसी की मेरी जानकारी है, वह रकम सत्तर हजार रुपये से अधिक है—दे कर रानीखेत में मकान खरीदा गया है और मैं आप की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि सिवायें इस के कि वह मकान एन्टी-नेशनल एक्टिविटीज का अड्डा है, उस का और कोई उपयोग नहीं है।

श्री अन्सार हरवानी : क्वेस्चन, क्वेस्चन।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं और इस नाते से कहना चाहता हूं कि आप उस की तमाम बातों को सुनें और फिर उस के बारे में निर्णय करें।

Mr. Speaker: The hon. Member will speak a little slowly. The Reporters are not able to take him down.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मुझे जलदी इसलिये करनी पड़ रही है कि आप ने समय की सीमा निर्धारित कर दी है और अगर आप मेरे समय को थोड़ा बढ़ा दें, तो मैं धीरे से और सन्तोष से अपनी बात को उपस्थित कर सकता हूं। मेरा सौभाग्य था कि वित्त मंत्री भी यहां बैठे हुए थे और वह सुन रहे थे कि किस प्रकार की अनियमिततायें चल रही हैं।

श्री कालिका सिंह (आजमगढ़) : माननीय सदस्य ने कह दिया कि वह मकान एन्टी-नेशनल एक्टिविटीज के लिये इस्तेमाल हो रहा है। यह बहुत आबजेक्शनेबल है। He said that the house in Ranikhet is being used for anti-national activities. But unless that is supported by some reliable authority or source.. *(Interruptions.)*

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य सुन तो लें।

श्री आसर (रत्नागिरि) : माननीय सदस्य क्यों वकालत कर रहे हैं।

Mr. Speaker: Very well. Hon. Member may continue.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरे पास इतने उदाहरण हैं और अगर आप चाहें, तो मैं उन सब को पढ़ कर सुनाऊं कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय के पैसे का दुरुपयोग वहां से सम्बन्धित लोगों की सम्पत्ति को क्रय करने के लिये किया गया है। मैं विशेष रूप से इस बात को यों कह रहा हूं कि हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जो करोड़ों रुपये इस विश्वविद्यालय को दिये जाते हैं, उन का क्या सदुपयोग हो रहा है इन तमाम घटनाओं को आप देखें, मैं तो चाहूंगा कि इस की तमाम विस्तृत सूचना में शिक्षा मंत्री महोदय को दूं, ताकि वह भी देखें कि उन के अन्तर्गत चलने वाले भारतवर्ष के एक विश्वविद्यालय में, जो इतना बड़ा ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, क्या क्या घटनायें घटती चली जा रही हैं। न सिर्फ उस में सम्पत्ति का क्रय इस प्रकार से किया जा रहा है, अपितु ऐसी घटनायें भी घटी हैं कि दो दो हजार बेकार पड़े सीमेंट को अलीगढ़ में फिर से पिसवाया गया और पिसवाने के पश्चात् उस में मिटी मिलाई गई और मिटी मिलने के पश्चात वे दो हजार सीमेंट की बोरियां दो हजार बोरियों से अधिक हो गई और उस सीमेंट का उपयोग विश्वविद्यालय के नवीन भवनों के निर्माण में किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस समय विश्वविद्यालय में जो भवन-निर्माण हो रहा है, उन को सुन कर आश्चर्य होगा कि विश्वविद्यालय के जो इस समय सब से बड़े इंजीनियर हैं, वह रामपुर के हैं और उन का नाम है श्री जब्बारखां। जहां तक उन की इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन का सम्बन्ध है, कोई इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन उन के पास नहीं है। उन के पास रामपुर रियासत में ओवरसियर की क्वालि-

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

फिकेशन थी, लेकिन निर्माण की आड़ में भी पैसा वहां से खींचा जा रहा है । जब से यह उपकुलपति विश्वविद्यालय में आये हैं, बहुत अधिक निर्माण-कार्य हो रहा है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री बिजिटर कमेटी में एक दो कुशल इंजीनियर भी रखें और इन उपकुलपति के समय में जितने भवन बने हैं, उन में कैसी ईंटें और कैसा सीमेंट इस्तेमाल किया गया है, इस की वह जांच करायें । मैं ने इस प्रकार की घटनायें देखी हैं कि भवन बनने के पश्चात् आध आध फीट दीवार फट गई । उस के बाद उस में सीमेंट लगाया गया दीवार को भरने के लिये, लेकिन सीमेंट कहां तक उस दीवार को रोक पाता ? इस का परिणाम यह हुआ कि फिर उस में दरार आ गई । यह पैसे का दुरुपयोग उस विश्वविद्यालय में चल रहा है, जहां मकानों के सम्बन्ध में इस प्रकार की चीज चल रही है । अब इस के लिये अच्छा यह हो कि जो वहां भवन बने हैं, इन भवनों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ओर से इंजीनियर गये हैं, उन की रिपोर्ट मंगाई जाये और देखा जाये कि उन्होंने क्या कहा है । मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मुझे पता लगा कि वह रिपोर्ट विश्वविद्यालय के आफिस से नष्ट कर दी गई है । अगर माननीय मंत्री चाहेंगे तो वह रिपोर्ट उन को प्राप्त नहीं हो सकेंगी, जो कि केन्द्र की ओर से भेजे गये इंजीनियरों ने तैयार कराई थीं ।

लेकिन सब से बड़ी बात जो मैं आप को कहना चाहता हूं, वह इस विश्वविद्यालय के अन्दर (एपायंटमेंट्स) नियुक्तियों के सम्बन्ध में है । इस के सम्बन्ध में किस प्रकार की अनियमिततायें बरती जा रही हैं, उस के थोड़े से उदाहरण में प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

Mr. Speaker: Order, order. A half-an hour discussion arises out of a question and the answers thereto. For whatever answers are not sufficiently clear, with respect to them, a half-an-hour discussion is allowed to clear up those answers and also to cover any relevant matters which could not be dealt with in the question. The hon. Member is making a series of allegations of all kinds of misappropriation, etc.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं संक्षिप्त भाषा में तीन बातों को कह देता हूं ।

Mr. Speaker: माननीय सदस्य को पहले सुनना चाहिये कि मैं क्या कह रहा हूं । Without these particulars being given, how can the hon. Minister answer? Assuming all these arise out of this question, even then he cannot answer. He has to get replies from the respective authorities concerned and then satisfy the House. It is unfortunate. With respect to those points, a detailed statement may be given and I will pass it on to the hon. Minister.

Shri Braj Raj Singh: More time is required for the discussion of this matter. If the allegations which have been made are true even to a remote extent, that is a very serious matter. We have got our nominee on the committee of the university.

Mr. Speaker: I am thinking of what can be done. Is he concluding? Whatever he wants to say, let him put in the form of a statement and place it on the Table of the House.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं संक्षिप्त सी भाषा में ये बातें कह देता हूं ।

Mr. Speaker: He may give the headlines; so far as the details are concerned, he may place them on the Table of the House.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): All these things require verification. Grave allegations have been made here. The Education Minister should place a statement on the Table of the House. We cannot verify them.

Shri Ansar Harvani: He is making sweeping allegations. A thorough investigation is necessary. A half-hour discussion will not be enough, because he has come out with a series of allegations without substantiating them.

Mr. Speaker: There need be no allegations and counter-allegations. Whether these allegations are individually true or not there is something against the Aligarh University, as is clear from the committee being appointed by the university itself to look into these matters.

This is not the first instance. A number of questions have been tabled from time to time; I have disallowed most of these questions except one, for the reason that a university is supposed to be autonomous and when once some disrepute comes over the university, it loses all its reputation. Therefore, I was very careful to avoid it. For 6 or 8 months, the hon. Member has been tabling question after question. I have rejected all those questions, except one. When I came to learn that they are themselves appointing a committee, I wanted to know what exactly the truth was and so I thought it would not be right for me to go on rejecting those questions endlessly. He is giving a number of things. He may give some headlines —some categories—and then he should close. I will ask the hon. Minister to make further enquiries into the matter. That is all that can be done at this stage. If Shri Harvani or Shri Mathur or some other hon. Member wants to put a question, I will allow them. This will come up in some other form. After he makes an enquiry, I am sure the hon. Minister will place a statement on the Table of the House.

Shri Braj Raj Singh: Let us have a longer discussion.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं सीमित भाषा में अपनी बात का उपसंहार किये देता हूं ।

जैसा कि मैं अभी निवेदन कर रहा था, यूनिवर्सिटी के पैसे से सम्बन्धित अधिकारी बहुत बड़े बड़े अपने भवन आज उनको बेच कर अनुचित लाभ उठा रहे हैं और दूसरी चीज यह कह रहा था कि रामपुर से, जहां के उपकुलपति हैं, इंजीनियर और दूसरे अधिकारी भंगा कर विश्वविद्यालय का निर्माण-कार्य चल रहा है और उस की आड़ में बहुत कुछ पैसा लिया जा रहा है । एक ओर तो यह स्थिति है । और दूसरी ओर स्टेट्समैन अखबार में देखने से यह पता चला कि गुलमर्ग में जो बहुत बड़ी आबजरवेटरी है, उस को भी अब वहां से हटा कर अलीगढ़ लाने का विचार है, ताकि इस आधार पर निर्माण का एक और बहुत बड़ा कार्य मिल जाये । लेकिन इस समय मैं आप को नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी हैडलाइन्ज में ही बात कहना चाहता हूं ।

पहले जो वहां रजिस्ट्रार थे, पीछे उन के साथ इस प्रकार की दैवी दुर्घटना घटी कि उन को लकवा या फालेज हो गया । फालेज होने के पश्चात् स्थिति ऐसी हुई कि वह न तो बोल सकते हैं और साथ ही उन का एक पैर और हाथ बेकार हो गया । लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को यह जान कर आश्चर्य होगा कि वहां के इंगलिश डिपार्टमेंट के हैड, डा० बोस से बिना पूछे हुए यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से अनुमति ली कि इन को एडीशनल प्रोफेसर के रूप में रखने की अनुमति दी जाये । मुझे इस बात का दुख है कि डा० देशमुख की जड़ में भी इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, जो कि देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं । वहां पर १२५० रुपये के लगभग जो प्रोफेसरों का ग्रेड होता है । आज एक लकवे के मारे व्यक्ति को जो कि न पूरी तरह बोल सकते हैं और न चल सकते हैं, प्रोफेसर का ग्रेड दिया जा रहा है और

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

वह तन्ख्वाह ले रहे हैं । इसी प्रकार पालिटेकनीक के जो प्रिंसिपल हैं, उनकी स्थिति यह है कि उन के मुकाबले में जब इन्टरव्यू हुआ, तो दो इस प्रकार के प्रतिनिधि भी आये, कि जिन के पास फारेन डिग्री थी और इन के पास कोई उस तरह की डिग्री नहीं थी । लेकिन वहां इस प्रकार की स्थिति पैदा की गई कि जो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त लोग थे उनकी उपेक्षा कर के पालीटैक्नीक के प्रिंसिपल पद पर श्री अब्बास को नियुक्त किया गया । इस तरह की बहुत सी घटनायें हैं जोकि यदि आप चाहें तो मैं आपको बतला सकता हूं ।

लेकिन अन्त में मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए आपका ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । एक सबसे बड़ी चीज है वह यह है कि विश्वविद्यालय का शिक्षा का जो एक स्तर होता है, उसका मापदंड विधिवत् स्थिर रहना चाहिये लेकिन वहां स्थिति इस प्रकार की है, उच्च अधिकारियों ने इस प्रकार के कांड किये हैं जिस में परीक्षा के अन्दर और विशेषकर इंजीनियरिंग की परीक्षा के अन्दर इस प्रकार की घटनायें घटी हैं जिन को कि किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है । एक लड़की है, उसके बारे में उन्होंने यह देखा कि फर्स्ट क्लास के मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो दूसरे किसी के समान मार्क्स रख कर यह कहा कि कापियों को रिएग्जेमिन कराया जाये, फिर से कापियां दिखवाई जायें, दूसरे परीक्षक रख कर यह काम करवाये जायें और इस प्रकार से उसको फर्स्ट क्लास दी गई । इसी तरह फेल होने वाले को पास किया जा रहा है । यदि आप इसके प्रमाण चाहते हैं तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं । यह उस विश्वविद्यालय का स्तर बनता जा रहा है ।

Dr. K. L. Shrimali: Has the hon. Member any particular name in view?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मुझे खुशी है कि आप ने मुझ से यह बात पूछी है और चाहा है कि मैं प्रमाण दूं या कोई केस बताऊं । लीजिये मैं बतलाता हूं :—

जून १९५६ में इंजीनियरिंग इंटरमीडियेट और डिपलोमा परीक्षाओं में प्रश्नोत्तर की कुछ विशेष कापियों को पुनः जांच करने के लिये आदेश दिया गया था। इसका यह कारण बताया गया था कि एक ही विषय के दो पत्रों के सफल उम्मीदवारों की प्रतिशतता में असमानता थी अतः यह आवश्यक समझा गया कि जिन पत्रों में कम प्रतिशत लोग पास हुए हैं उन की पुनः जांच की जाये । इस दुबारा जांच का वास्तविक कारण यह था कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय की लड़की को इंटरमीडियेट में कुछ नम्बर कम होने के कारण प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं हुई थी और एक उच्चाधिकारी का सम्बन्धी इंजीनियरिंग डिपलोमा की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ था । परीक्षक के निर्णय में इस साधारण सी गलती के कारण प्राधिकारियों ने उस द्वारा दिये गये अंकों को बदल देना आवश्यक समझा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये पहले परीक्षकों को हटाये बिना नये परीक्षक नियुक्त किये गये और इसके परिणाम स्वरूप सारी परीक्षा पद्धति भ्रांतिपूर्ण और आपत्तिजनक बन गई ।

यदि माननीय मंत्री और भी इस तरह के उदाहरण चाहें तो मैं उनको और भी दे सकता हूं । चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं उनको एक ही उदाहरण दे रहा हूं । यह उस विश्वविद्यालय की स्थिति है जोकि भारतवर्ष का गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है । जो शिक्षा का मंदिर है, वहां से तो भ्रष्टाचार को कम से कम आप दूर करने का प्रबन्ध करें ।

अन्त में मैं जोर दे कर कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि विश्वविद्यालय की कमेटी इनक्वायरी करे, आप विजिटर कमेटी नियुक्त

करें जिसमें स्वतंत्र विचारों वाले लोग हों और वे इस सारे मामले की जांच करें और जांच करने के बाद रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिये । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जैसी निष्पक्ष विजिटर कमेटी नियुक्त की गई थी, उसी तरह से अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी कमेटी नियुक्त होनी चाहिये ।

Mr. Speaker: Whatever details he has got, let him write them down and pass it on to the hon. Minister.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं मेज पर रख दूंगा ।

Shri Ansar Harvani: I would like to ask of my hon. friend only two questions. Firstly, he has mentioned a number of allegations about.....

Shri Braj Raj Singh: On a point of order. Shri Harvani is our nominee on the Aligarh University. So he is himself an interested party in the University. Can he be allowed to take part in the discussion?

Shri Ansar Harvani: I take very strong exception to the remark that I am becoming a party to the various allegations that have been made.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): There is no allegation against him.

Shri Ansar Harvani: The real facts of the case have to be examined.

Shri Harish Chandra Mathur (Pali): Shri Harvani is not personally interested. He is a member of this House and he has every right to participate in the discussion.

Shri Ansar Harvani: As a representative and member of this House it is my duty to keep this House fully informed.

Mr. Speaker: Let there be no recriminations. The hon. Member has no financial interest in the business. He is our member there and he knows what exactly is happening. Some allegations of a serious nature have been made about the University. He must have an opportunity to tell the House what exactly has happened. The decision of the House is not in the hands of either one or the other Member. The House as a whole will take a decision on this matter. Shri Harvani should be as brief as possible. Whoever has given notice can ask a question or two, and the hon. Minister will then reply.

Shri Khushwaqt Rai (Kheri): In a half-an-hour discussion a member who raises the discussion puts certain questions to the Minister. But it is not open to any member to put questions to the Member who raises the discussion. Now Shri Harvani is putting questions to the Member who has raised the discussion.

Mr. Speaker: He can put a question himself regarding this to the Minister.

Shri Ansar Harvani: I would like to ask the hon. Minister one question. Is it or is it not a fact that the moment the facts of certain financial irregularities came to the notice of the Aligarh University, that University appointed a committee consisting of so many eminent persons like Shri D. C. Chatterjee, former Vice-Chancellor of the Rajasthan University and Shri Wadia, a very prominent member of the Rajya Sabha, a representative of the Finance Ministry and a representative of the Education Ministry to look into it?

Allegations have been made about the building which has been sold by the Secretary of the Education Ministry. Usually this House never discusses the conduct of the permanent servants or permanent secretaries of the Government. But unfortunately the name of the Education Secretary was mentioned. I want to ask the hon. Education Minister whether it is a fact that the University Engineer had given the valuation of that building and had given that price.

[Shri Ansar Harvani]

I would also like to ask another question. My hon. friend, in his zeal, has mentioned that the house, which has been purchased for being used as a holiday house by the teachers and students in Ranikhet, is being used as a centre of anti-national activities. I take strong exception to it. I would like to say that Aligarh University today is the greatest citadel of democracy. Aligarh University is fighting for nationalism and no other university can compete with it.... (*Interruption*).

18.16 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I will allow the hon. Member to ask a question or two only. Shri Jamal Khwaja.

Shri Jamal Khwaja (Aligarh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, a number of allegations have been made. I have no desire to say anything in regard to those allegations, but since the name of Shri A. M. Khwaja has been mentioned and he happens to be my father, I thought that on a point of personal explanation I would say just a word or two.

We know that no legal action can be taken against anything that is said in the House. But I would like to ask the hon. Member whether he knows that he can make himself.... (*Interruption*). I would ask the hon. Deputy-Speaker whether the hon. Member knows that he can make himself look ridiculous by giving credence to charges about which he has been given the most wild and misinformed reports. In all humility I would like to make a statement. Although legally speaking the actions of a person have nothing to do with his heirs so long as he is alive. I would like to make an offer or a challenge. Let the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri, suggest any honest and impartial person in India—any honourable impartial person—and let the case be referred to him. If that impartial person concludes that Shri Khwaja—I do not know about the other cases that the hon. Member has mentioned, but I know about this case—has done any immoral thing, quite apart from any illegality, I am prepared to resign my seat in the Lok Sabha here and now. I want to know whether he is prepared to resign his seat.... (*Interruption*). I want to know in all humility, whether Shri Prakash Vir Shastri is prepared to resign his seat. I am prepared. Let this impartial judge and authority.... (*Interruption*).

An Hon. Member: Can he throw a challenge in the Lok Sabha?

Shri Jamal Khwaja: He should give an undertaking in the House just now that he will resign his seat. I want this assurance from him in this House. I want a straight answer.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Mathur.

Shri Prakash Vir Shastri *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: I have called Shri Mathur.

Shri Harish Chandra Mathur: I have only two questions to ask. A sub-committee has been referred to by Shri Harvani, which was appointed to enquire into the affairs of the Aligarh University. This committee was appointed quite a long time back. Why has this committee not at all functioned? Who stands in the way of the functioning of that committee? Why was it made defunct?

Another question which I would like to ask the hon. Minister is this. It is obvious from the statement laid on the Table of the House in answer to this question that the Aligarh University has stubbornly disregarded and ignored the Ministry for quite a number of years. What are the reasons....

An Hon. Member: How do you know?

Shri Harish Chandra Mathur: It is obvious from the answer which has been given to this question. If you go and look into the statement, you will find that for about seven to eight years the Ministry had been wanting to get some information and secure certain reports, but in spite of a committee having been appointed it was not functioning all these years and the Ministry was not getting any satisfactory reply. How is it that this Ministry has tolerated this stubborn attitude of this university disregarding it all the seven years? What were the reasons, who were the people who were responsible for it, and how does the Ministry itself explain its own attitude in this matter? I am asking the Ministry how they explain their attitude.

Pandit Thakur Das Bhargava (Hissar): With your permission, I want to put one very small question. I want to know if the Vice-Chancellor is a member of that committee, and he will also sit in judgment over his own cause.

Mr. Deputy-Speaker: Would the hon. Minister like to answer just now, or does he want to ascertain the facts?

Dr. K. L. Shrimali: As I indicated to you, I am in a little difficult position.

Shri Braj Raj Singh: No difficult position.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. He knows whether he is in a difficult position or not. How does the hon. Member on this side know?

Dr. K. L. Shrimali: Some of these matters were brought to my notice by Shri Prakash Vir Shastri a few months back. Then I made certain preliminary enquiries about these matters, and I assured him that all these matters would be looked into and examined.

It is true that some of these objections have been raised in the last eight to ten years by the Comptroller and Auditor-General, and it is also true that some committees were appointed and they did not function. In this matter, as you are aware, the university is an autonomous body; it is created by an Act of Parliament, and it functions within that framework, and Government cannot possibly interfere in its day to day administration. But, since I thought that the points that were raised by the Comptroller and Auditor-General and some of the points that were raised by Shri Prakash Vir Shastri in his letter to me and in the question that he had put in Parliament were rather serious, I talked to the university authorities, and they have now appointed a committee which is an impartial and independent committee. The persons in this committee are people of outstanding ability, about whose integrity and independence we cannot have any doubt.

Shri Raghunath Singh: Can we know their names?

Dr. K. L. Shrimali: Shri G. C. Chatterjee is the Chairman. Other Members are: Professor A. R. Wadia, a Member of Parliament, Shri Kartar Singh Malhotra, former Accountant-General, Posts and Telegraphs, the Joint Secretary of the Ministry, Shri R. P. Naik, is the Member-Secretary of this committee. Their terms of reference are wide, and I expect they will examine all the points that have been raised by my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri and also the objections which have been raised by the Comptroller and Auditor-General.

The terms of reference are:

(1) To enquire into the financial transactions of the University from 1951-52 to date with special reference to the Audit objections relating to the accounts of these years and steps, if any, taken by the University to meet these objections;

(2) To enquire into the recruitment, appointment and promotion of the teaching and administrative

[Dr. K. L. Shrimali]

staff of the University and the admission of students to the University since 1951-52 and to report on the same;

(3) To suggest suitable measures of reforms necessary for the efficient functioning of the University.

The difficulty is that unless these matters which have been raised by Shri Prakash Vir Shastri are looked into, I am not in a position either to accept them or to deny them. The University has given me an assurance that this committee has been appointed . . .

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Minister been given any idea as to how soon the committee would be able to finish their work?

Dr. Ram Subhag Singh: And when was it appointed?

Shri Kalika Singh: Are these points covered by the terms of reference?

Mr. Deputy-Speaker: Yes, they are covered.

Dr. K. L. Shrimali: All the objections that have been raised will be covered by these terms of reference. This is a very high-powered committee, an independent committee, and I have no doubt in my mind that it will make a thorough investigation into all the charges which have been made by my hon. friend.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं शिक्षा मंत्री जी से इस सम्बन्ध म एक स्पष्टीकरण चाहता हूं यदि वे कर सकें । जैसा मैं ने अपने वक्तव्य में कहा था, यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार वाइस चान्सलर भी उस कमेटी का सदस्य होता है । और जब वाइस चान्सलर उस कमेटी में बैठा होगा तो यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित अधिकारी या व्यक्ति निर्भीक या स्वतंत्र भाषा में अपनी सम्मति दे सकेंगे, इसमें मुझे संदेह है । इस लिये मेरा अपना निवेदन यह है कि जब तक यह एन्क्वायरी हो, वाइस चान्सलर उस स्थान से हटा दिये जायें ।

Dr. K. L. Shrimali: I was going to answer that point also. It is true that if it is a university committee, the Vice-Chancellor naturally can sit on that committee. But I have no doubt in my mind that the Vice-Chancellor, if there are any charges against himself, as the hon. Member has pointed out, will certainly have the discretion not to sit on this committee; for, if there are certain charges against him, as the hon. Member has pointed out, I am quite definite that the Vice-Chancellor will not sit on this committee. And if this committee is not allowed to function properly, after all, there is nothing to prevent us from having a Visitor's committee. Government can always advise the Visitor to appoint his own committee. Therefore, in my opinion, at this stage, it would be advisable for this committee to function.

With regard to the time, though no time-limit has been set, yet we have the Joint Secretary of this Ministry as the member-secretary of this committee, and we are doing everything that is possible to examine all the points that have been raised.

If a certain allegation is made against a university, it is our duty to ensure that all these allegations are cleared; if there are any people who are responsible for embezzement or defalcation, they should be brought to book. Nobody has any right to play with public funds; nobody has any right to misuse public funds. And of all places, a university is the place where we should have people of the highest integrity and character, and a university should be the last place where such things should have happened, if there is any substance of truth in what the hon. Member has said, the matter is serious, and I can assure the House that Government will take all possible steps to ensure that the university is cleaned of all the charges that are levelled against

it. At this stage, it is difficult for me to say when this report will be submitted, but I hope, and it will be our endeavour, to expedite submission of this report. If the hon. Member has any other information, he may kindly pass it on to me, and it will be forwarded to the university authorities, who will forward it to the committee concerned.

I am afraid I am not in a position to say anything more at this stage, because certain things have been said on the floor of the House here, and it is not possible for me either to deny them or to accept them, and I can only await the report of this committee.

Shri Harish Chandra Mathur: May I know why the previous committee was not permitted to function, whether those obstructive things are still there, and why the Ministry did not take action before?

Mr. Deputy-Speaker: No questions have been answered, because it is not possible to answer any questions at this stage. Now, the only thing is whether this House wants that the Minister should answer all those allegations after getting information at this stage from the university; I am afraid that that would be the information given by the Vice-Chancellor himself. Then, should the House accept that? . . .

Shri U. L. Patil (Dhulia): Shri Harish Chandra Mathur's question should be answered.

Shri Harish Chandra Mathur: My question is not regarding any allegations. My question is against the Ministry itself. Why did they not function all these eight or ten years, when the things were brought to their notice? A sub-committee was appointed by the university earlier, but that committee did not function, in spite of the Ministry asking them to function. That were the obstructive factors? Who were the obstructers? Have these obstructions been removed now? My allegation is again the Ministry itself.

Shri D. C. Sharma: It has been the convention in this House ...

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. There should be no new questions now.

Shri D. C. Sharma: It has been the convention of this House not to level charges against persons who are not present here, but that convention has been violated today.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member has stood up after all the things have been said now. Should I withdraw all that? Or else, what should I do now? He has sat silent and waited till everything had been said.

Dr. K. L. Shrimali: With regard to the question raised by my hon. friend Shri Harish Chandra Mathur the position is that Government do not like to interfere in the day-to-day administration of the university as far as possible. When this matter was brought to the notice of Government by the Comptroller and Auditor-General, we advised the university to appoint a committee.

They did appoint a Committee Unfortunately, that Committee did not meet. Another Committee was also appointed. Unfortunately, that Committee also did not meet.

Shri Braj Raj Singh: Why not?

Dr. K. L. Shrimali: The University has no explanation for it. They thought they would be able to do it, they would receive the report of the Comptroller and Auditor-General, examine it and clear up all the objections which might be raised by the Comptroller and Auditor-General. That sometimes happens. The University felt that they would be able to deal with them.

Shri Braj Raj Singh: What have they been doing all this time?

An. Hon. Member: Sleeping.

Dr. K. L. Shrimali: As I said, the University is an autonomous body, and the House does not expect Government to interfere in the day-to-day administration of the University. As far as possible, we would like the University to function for themselves in all these matters. It was only when we found that the matter was not being cleared up, the University was advised to appoint a Committee. I think the House should wait for the findings of the Committee before passing any judgment on this matter.

Shri Braj Raj Singh: Who knows? The Committee may not function.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I agree with this position that the House should wait till the Committee has come to certain conclusions. It is not necessary that the House should accept those recommendations or decisions arrived at by the Committee, whatever they are. If the House then feels that the Education Ministry should advise the Visitor to appoint a Committee or there should be another discussion here or something else, it can act accordingly. But before the report is received, the Minister is not able to answer any of these allegations. I would advise the hon. Mover to give all those particulars of instances that he has got. He might, as advised by the hon. Speaker, place them on the Table of the House and then they would be passed on to the Minister who, in his turn, would send them to the Committee. Then we will have definite and positive answers so far as those allegations are concerned. Then we can consider whether any of them had been rightly investigated and gone into or not. At this moment, if any other demand is made, if we just force the Minister and say that he should straightway get answers, those answers, as I said earlier, would be based on information supplied by the Vice-Chancellor himself. Therefore, the House would not be satisfied with those answers. Then hon. Members would say that the Vice-Chancellor himself was guilty. It will be said: 'We had levelled charges against him. He is the man who has given the reply'. There is no other source from which the Minister can get information just at present. He cannot go and investigate himself.

Therefore, it is better that we wait till the Committee decides whatever it likes. Let it come to a decision. Then we will see.

Shri U. L. Patil: Will the report of the Committee be placed on the Table of the House?

Mr. Deputy-Speaker: Yes.

Dr. K. L. Shrimali: It is not possible for me to make any commitment at this stage. I would request you to allow me to adjudge the report before placing it on the Table.

Mr. Deputy-Speaker: I am not committing myself or the House as to whether that would be placed on the Table or not, but because allegations have been made, the Minister shall answer those allegations. I suppose he shall have no objection, though his information then would be based on the conclusions arrived at by the Committee. When that information is in possession of the House, the House might proceed in the way it likes under the circumstances.

Now this discussion is over.

18.33 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 3, 1960/Phalguna 13, 1881 (Saka).